THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) A statement showing the Inland Air Travel Tax realised and the arrears thereof outstanding from Private Airlines is enclosed (*See* below).

(c) Show Cause notices demanding the payment of arrears of Inland Air Travel Tax have been issued to the private taxi operators against whom the arrears are outstanding.

Statement

Amounts of Inland Air Travel Tax realised and the arrears against Private Air Taxi Operators

S. No.	Name of the Carrier	Amount realised	Amount outstanding
1.	M/s. India International Airways Pvt. Ltd., New Delhi.	Rs. 11.94 lakhs	Nil.
2.	M/s. Delhi Gulf Airways Service Pvt. Ltd., New Delhi.	Rs. 2.70 lakhs	Nil.
3.	M/s. Trans Bharat Aviation Pvt. Ltd., New Delhi.	Rs. 7.86 lakhs	Nil.
4.	M/s. Udan Research & Flying Institute, Indore	Rs. 0.18 lakhs	Nil.
5.	M/s. Jagson Airlines, New Delhi . .	Rs. 7.80 lakhs	Rs. 11.31 lakhs upto March, 93.
6.	City link Airways, New Delhi . . .	Not Paid	Rs. 60.16 lakhs upto February, 93.
7.	Continental Aviation Pvt. Ltd., Bombay .	Not Paid	Rs. 35.83 lakhs upto November, 92.
8.	M/s. East-West Airlines, Bombay . .	Not Paid	Rs. 14.28 crores upto February, 93.
9.	M/s. Jet Airways, Bombay . . .	Rs. 1.05 lakhs	Nil.
10.	M/s. Saraya Aviation, Delhi . . .	Rs. 0.02 lakhs	Nil.

उत्तर प्रदेश को संस्थागत ऋणों का वितरण

1899. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में संस्थागत ऋण का वितरण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त संस्थागत ऋणों का जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश में संस्थानों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा उपलब्ध कराए गए पुनर्वित्त सहायता की जानकारी चाहते हैं । नाबार्ड, उक्त राज्य में कृषि और सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये चार ग्रामीण वित्तपोषक एजेंसियों अर्थात् वाणिज्यिक बैंकों, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि०, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और उत्तर प्रदेश सहकारी

बैंक को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता रहा है। राज्य को पुनर्वित्त का प्रवाह सदा उच्चतम रहा है। पिछले तीन वर्षों का पुनर्वित्त का स्तर और वार्षिक प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित है :–

(लाख रुपए)

वर्ष	योजनागत ऋण के तहत नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त संवितरण		(2) की तुलना में (3) का प्रतिशत हिस्सा
	अखिल भारत	उत्तर प्रदेश	
1	2	3	4
1990-91	1,90,217	33,949	17·85
1991-92	2,05,436	38,176	18·58
1992-93	2,35,909	41,224	17·47

(ग) उत्तर प्रदेश में योजनागत ऋण के तहत नाबार्ड द्वारा संवितरित पुनर्वित्त के जिलावार ब्यौरे नाबार्ड से एकत्र किए जा रहे हैं और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बकाया केन्द्रीय-कर

1900. **श्री अजीत जोगी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार/संघ शासित क्षेत्र-वार आय कर और अन्य केंद्रीय करों की कितनी धनराशि बकाया थी ;

(ख) उक्त तारीख को प्रत्येक केन्द्रीय कर से संबंधित कितने मामले राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार न्यायालयों में लम्बित पड़े थे ;

(ग) सरकार द्वारा इन करों की बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) बकाया राशि से संबंधित मुख्य बाकीदारों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में महिला बैंक की स्थापना

1901. **श्री अजीत जोगी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक को मध्य प्रदेश में महिला बैंक की स्थापना करने हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान उस राज्य में कितने लाइसेंस दिए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में अन्य राज्यों की क्या स्थिति है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

1902. [*Transferred to 20th August*, 1993.]

Non-Functioning of Branch Offices of NHB

1903. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI N. GIRI PRASAD:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the National Housing Bank has taken a decision to implement the National Housing Plans and Schemes throughout the country without having any branch offices;

(b) if so, the details thereof; and